



9000 से ज्यादा जवान राहत-बचाव कार्य में लगे, (सेना, वायुसेना, बीआरओ, आईटीबीपी)

13 टीमों एनडीआरएफ की बारिश से हुई तबाही के बाद राहत और बचाव कार्यों में लगी हैं

केंद्र सरकार ने आपात बैठक कर बचाव ऑपरेशन तेज करने के लिए निर्देश

केंद्र से मिलेगी एक हजार करोड़ की सहायता

प्रधानमंत्री और सोनिया ने हवाई सर्वे कर लिया उत्तराखंड के हालात का जायजा

आपदा पीड़ितों के क्लेम जल्द निपटाएंगी बीमा कंपनियां

● अमर उजाला ब्यूरो

- पीएम आवास पर सीएम और आपदा मंत्री के साथ पीएम की हुई बैठक
- आपदा में मृतकों के परिजनों को दो लाख और घायलों को 50 हजार रुपये की मदद

केंद्र ने बुलाई बैठक

नई दिल्ली/देहरादून। आपदा से निपटने को केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को एक हजार करोड़ रुपये की मदद की घोषणा की है। बुधवार को राज्य के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने के बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसकी घोषणा की। उन्होंने आपदा में मृत व्यक्तियों के परिजनों को दो-दो लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपये की सहायता तत्काल मुहैया कराने की भी घोषणा की है।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी के साथ बुधवार दोपहर राज्य के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई जायजा लिया। यहां से लौटने के बाद पीएम आवास पर राज्य के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, आपदा मंत्री यशपाल आर्य और कृषि मंत्री हरक सिंह रावत तथा मुख्य सचिव सुभाष कुमार के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने राज्य को केंद्र की तरफ से आर्थिक सहायता के अलावा राहत और बचाव कार्य में हर संभव मदद मुहैया कराने का आश्वासन दिया।

इसके पहले सुबह 9.30 बजे मुख्यमंत्री ने खुद भी इन मंत्रियों के साथ आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। उन्होंने केदारनाथ में करीब 45 मिनट रुक कर राहत और बचाव कार्य का निरीक्षण किया। केदारघाटी का जायजा लेने के बाद उन्होंने बटनीनाथ

उत्तराखंड में हुई भीषण तबाही के हालात की समीक्षा के लिए केंद्र ने बुधवार को उच्चस्तरीय बैठक बुलाई। कैबिनेट सचिव अजीत सेठ की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में रक्षा सचिव, एनडीआरएफ के प्रमुख ने भी हिस्सा लिया। बैठक के बाद वायुसेना को बचाव ऑपरेशन में और तेजी लाने का निर्देश दिया गया। वहीं, गृहमंत्री शिंदे ने उत्तराखंड और हिमाचल में आई प्राकृतिक आपदा को व्यापक बताया। जरूरत पड़ने पर बचाव कार्य में लगे वायुसेना के हेलीकाप्टरों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। शिंदे ने कहा कि केंद्र सरकार हालात पर लगातार नजर रखे हुए है।

घाटी के हालात का जायजा लिया। वहीं से वे दिल्ली चले गए। जहां 5.30 बजे उनकी प्रधानमंत्री के साथ बैठक हुई।



'सौ साल में नहीं हुई ऐसी त्रासदी'

नई दिल्ली (ब्यूरो)। उत्तराखंड में बाढ़ की त्रासदी को लेकर मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने बुधवार को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात कर उन्हें प्रदेश के भयावह हालातों की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री से प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए सहायता भी मांगी। उन्होंने कहा कि हिमालय में बसे किसी प्रदेश में सौ साल में ऐसी त्रासदी नहीं हुई है। इससे निपटने में समय लगेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के हजारों नागरिकों और तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सैकड़ों लोग मारे गए हैं। एक शहर नहीं कई जिले तबाह हो गए हैं। कई गांव के गांव डूब गए हैं। हजारों लोग लापता हैं। इसलिए आंकड़ों का अभी सटीक पता लगाया नहीं जा

- बहुगुणा ने कहा, उत्तराखंड की आपदा से उबरने में लगेगा समय

सकता। साथ ही बहुगुणा ने कहा कि केदारनाथ मंदिर पूरी सुरक्षित है। राज्य की भयावह स्थिति में केंद्रीय मदद के लिए दिल्ली आए मुख्यमंत्री ने मीडिया से बात करते हुए प्रदेश की जनता और यात्रियों को धैर्य रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि 100 साल में इतना कहर नहीं बरपा। जितना अब प्रदेश में हुआ है। प्रदेश की 500 से ज्यादा सड़कें टूट गई हैं। 200 के करीब पुल बह गए हैं। दूरदराज क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित निकालना बड़ी चुनौती है। जहां भोजन पानी भी नहीं पहुंच पा रहा है।

नई दिल्ली (ब्यूरो)। उत्तराखंड, हिमाचल और उत्तर प्रदेश सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में बाढ़ का प्रकोप जारी है। ऐसे में जान-माल की क्षति के अलावा घरों और वाहनों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। वाहनों और घरों के लिए बीमा कंपनियों से क्लेम लेकर नुकसान की कुछ हद तक भरपाई की जा सकती है। प्राकृतिक विपदा की इस घड़ी में कंपनियां भी क्लेम प्रक्रिया को जल्द निपटाने और सरल करने का दावा कर रही हैं। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के चीफ (अंडरराइटिंग एंड क्लेम) संजय दत्ता ने अमर उजाला को

बताया कि प्राकृतिक आपदा की इस घड़ी में हमारी कोशिश यह रहेगी कि वाहनों पर क्लेम देने की प्रक्रिया ज्यादा तेज और आसान कर दी जाय। इसके तहत हम कम दस्तावेज और प्रमाणीकरण पर जोर देंगे। बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के चीफ टेक्निकल ऑफिसर विजय कुमार ने कहा कि बाढ़ में क्षतिग्रस्त मोटर बीमा पर क्लेम सामान्य क्लेम की तरह ही ग्राहकों को मिलेगा। यह बात ध्यान देने की है, ग्राहक डूबी हुई गाड़ी को किसी भी तरह स्टार्ट न करें। ऐसी कोशिश से इंजन खराब हो जाता है, जो कि क्लेम का हिस्सा नहीं होगा।

गंगा नदी को केंद्र सरकार घोषित कटे राष्ट्रीय धरोहर : उमा भारती

नई दिल्ली (ब्यूरो)। भाजपा उपाध्यक्ष उमा भारती ने गंगा की पवित्रता अक्षुण्ण रखने और उसकी अवरल धारा को बनाये रखने के लिए ठोस पहल पर जोर देते हुए सरकार से गंगा नदी को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किये जाने की मांग की है। गंगा समग्र अभियान के तहत आयोजित सम्मेलन में बुधवार को पारित प्रस्ताव में कहा गया कि गंगा नदी को बिना समय गंवाये राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए। इस प्रस्ताव में उत्तराखंड में आए जल प्रलय की चेतावनी को समझने और इससे सबक लेने की जरूरत पर बल दिया गया। उमा भारती ने उत्तराखंड में हुई तबाही को गंगा के प्रवाह मार्ग को बाधित करने का दुष्परिणाम बताया है। उन्होंने कहा कि राज्य की रक्षक धारी देवी मंदिर से की गई छेड़छाड़ से रुष्ट गंगा अपना रौद्र रूप इस जल प्रलय के जरिए दिखाया है।

सरकार ने 9 जत्थों की कैलाश मानसरोवर यात्रा रद्द की

नई दिल्ली। सरकार ने बुधवार को 2 से 10 नंबर के जत्थों की कैलाश मानसरोवर यात्रा रद्द कर दी है। यह कदम उत्तराखंड में बाढ़ और मूसलाधार बारिश की वजह से यात्रा मार्ग को हुए भारी नुकसान को देखते हुए उठाया गया है। अल्मोड़ा और तवाघाट के बीच कई स्थानों पर सड़क बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। साथ ही कई प्रमुख ब्रिजों को भी नुकसान पहुंचा है। कई स्थानों पर भूस्खलन के चलते तवाघाट के पीछे पैदल रास्ते को भी बुरी तरह से क्षति पहुंची है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि प्रदेश और स्थानीय प्रशासन के अनुसार, हालात के सही होने में एक महीने का वक्त लग सकता है। यात्रियों की रक्षा और सुरक्षा को देखते हुए मंत्रालय ने इस साल बैच नंबर 2 से 10 की कैलाश मानसरोवर यात्रा को रद्द करने का फैसला लिया है। एजेंसी

किन बातों का रखें ध्यान

- 1 डूबी और क्षतिग्रस्त गाड़ी को किसी भी तरह स्टार्ट न करें, इंजन खराब होने पर उसका क्लेम नहीं मिलेगा।
- 2 गाड़ी के बहने और न मिलने के सुबूत अपने पास रखने की कोशिश करें।
- 3 आपदा से क्षतिग्रस्त गाड़ी के प्रमाण के लिए फोटो आदि को भी तैयार रखें।
- 4 घरों के लिए प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा पर बीमा पहले से कराना होता है।